

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 11 अगस्त, 2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजनान्तर्गत **₹75.00 लाख (₹ पचहत्तर लाख मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3- धनराशि का आहरण कर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी, तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा व्यय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च 2011 के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) करते हुए किया जायेगा। अगली किश्त की धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब पिछली किश्त का व्यय विवरण प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, तथा प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, यदि नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक: 31.03.2012 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च 2011 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

7- धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त रिबेट की धनराशि उन्हीं संस्थाओं को दी जा रही है जिनका चयन/पंजीकरण खादी ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार/खादी बोर्ड उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया गया हो। रिबेट की धनराशि का लाभ प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सूची व इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का विवरण भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00-आयोजनागत, 800-अन्य व्यय, 03-खादी वस्त्रों की विक्री पर छूट -00-, 50-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या:295/XXVII(2)/2010,दिनांक: 03 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1422(1)/VII-II-11/16-खादी/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।